

इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या 2752
21 मार्च, 2013 को उत्तर के लिए

देश में इस्पात का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2752. श्री देवेन्द्र गौड़ टी० :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में इस्पात का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उपरोक्त में से प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से संबद्ध खानों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त उपक्रमों को दी गई खानें उनके उत्पादन-लक्ष्य की पूर्ति हेतु पर्याप्त हैं; और
- (घ) यदि नहीं, तो ऐसी कंपनियों को खान उपलब्ध कराने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए हैं या करने का विचार है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क): इस्पात मंत्रालय के अधीन इस्पात का उत्पादन करने वाले दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) हैं अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)।

(ख): सेल कैप्टिव इस्तेमाल के लिए झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 9 लौह अयस्क खानों, 7 फ्लक्स खानों (लाइमस्टोन और डोलोमाइट) तथा 3 कोयला खानों का संचालन कर रहा है। इनके अतिरिक्त सेल के पास छत्तीसगढ़ के बाराद्वार में रावघाट आयरन ओर डिपॉजिट तथा डोलोमाइट डिपॉजिट हैं और झारखंड में 2 कोकिंग कोल ब्लॉक यथा टसरा और सीतानाला हैं। आरआईएनएल के पास कोई सम्बद्ध लौह अयस्क अथवा कोयला खानें नहीं हैं लेकिन इसके पास आंध्र प्रदेश में 4 फ्लक्स खानें हैं (जिनमें से डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मेंगनीज और सैंड की एक-एक खान है)।

(ग) और (घ): सेल लौह अयस्क संबंधी अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने कैप्टिव स्रोतों से कर रहा है। कैप्टिव और घरेलू स्रोतों से कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता के कारण कोकिंग कोल के संबंध में सेल की लगभग 75 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति आयातों से और लगभग 25 प्रतिशत कोकिंग कोल से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति घरेलू सप्लाई से की जाती है। आरआईएनएल लौह अयस्क संबंधी अपनी आवश्यकता की पूर्ति घरेलू सप्लाई से और कोकिंग कोल संबंधी अपनी आवश्यकता की अधिकांश आपूर्ति आयातों से कर रही है। कुल मिलाकर ये कंपनियां अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा कर रही हैं। तथापि, इन कंपनियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों से नई खानों का आबंटन करवाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक उपाय किए जाते हैं।
